

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 214 राँची ,ग्रुवार

25 वैशाख 1936 (श॰)

15 मई, 2014 (ई॰)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

12 मई, 2014

- 1. उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू का पत्रांक- 1592, दिनांक 20.10.2012
- 2. अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के आदेश ज्ञापांक-375, दिनांक 18.01.2012
- 3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-11520, दिनांक 30.11.2013

संख्या-5/आरोप-1-490/2014 का-4283--श्री पवन कुमार मंडल, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक 738A / 03, गृह जिला- भागलपुर), अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद-सह-तत्कालीन नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, पलामू के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू के पत्रांक- 1592, दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 के द्वारा प्रपत्र- 'क' मे आरोप प्रतिवेदित है। आरोप पत्र प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को संबोधित है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये है:-

- 1. अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के आदेश ज्ञापांक-375, दिनांक 18 जनवरी, 2012 के द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2012 को मनरेगा कूप लाभुक श्री जग्गू भुईंया, ग्राम+पंचायत- होटाई, टोला- चिरचिरिया टांड, प्रखण्ड- पांकी के आत्महत्या प्रकरण में गठित झारखण्ड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के तीन सदस्यीय समिति के जाँच प्रतिवेदन में आरोप लगाया गया है कि आरोपी पदाधिकारी ने रास्ता बेहद खराब रहने तथा उग्रवादी का भय बताकर क्षेत्र में जाने से रोकने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया।
- 2. जाँच कार्य पूरा होने से पूर्व ही मनरेगा नोडल पदाधिकारी वगैर सूचना दिये ही गायब हो गये। दूरभाष से सम्पर्क करने पर उन्होंने बताया कि मैं राँची पहुँच चुका हूँ।

तत्पश्चात् प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री मंडल से विभागीय पत्रांक-11520, दिनांक 30 नवम्बर, 2013 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री मंडल ने पत्रांक-90/भू0सु0, दिनांक 1 फरवरी, 2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री मंडल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के अनुसार जाँच समिति में श्री मनोज कुमार, श्रीमती वायलेट कच्छप एवं श्री विकास कुमार मुण्डा सिम्मिलित थे। उन्होंने भूलवश श्री मंडल के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित किया था। सिमिति के अध्यक्ष, श्री मनोज कुमार एवं सदस्य, श्रीमती वायलेट कच्छप द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को संसूचित किया गया है कि श्री मंडल ने जाँच सिमिति को पूर्ण सहयोग दिया था। सिमिति के सदस्य श्री मंडल को व्यक्तिगत रूप से नहीं पहचान पाये थे, जिस कारण उनके विरूद्ध सिमिति ने भूलवश आरोप लगाया था। सिमिति के सदस्यों ने उन्हें आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की है। श्री मंडल के अनुसार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पांकी एवं थाना प्रभारी, पांकी के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि वे मनरेगा सिमिति के साथ उपस्थित थे एवं जाँच में सहयोग किया था। लोकपाल मनरेगा, पलामू श्री शिवशंकर प्रसाद के पत्र से भी स्पष्ट है कि वे सिमिति के सदस्यों के साथ थे तथा जाँच में सहयोग कर रहे थे।

उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू ने भी राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त को संबोधित पत्र में भी श्री मंडल के विरूद्ध लगाये गये आरोप को यथोचित नहीं माना है।

श्री पवन कुमार मंडल के विरूद्ध प्राप्त आरोप, उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया है कि श्री मंडल समिति के साथ थे तथा जाँच में समिति के सदस्यों को सहयोग कर रहे थे। जाँच समिति के

सदस्यों ने भूलवश श्री मंडल के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित किया था। अतः श्री मंडल को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री पवन कुमार मंडल, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।
